*अभिशासन के माध्यम से विश्वास का निर्माण: दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण का आधार**

- एम. राजेश्वर राव

उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन, कार्यकारी निदेशक, बोर्ड के अध्यक्ष, एआरसी के एसीबी और एआरसी के एमडी और सीईओ, आरबीआई के मेरे सहकर्मियो, देवियो और सज्जनो,

एआरसी में अभिशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता करने के लिए आज आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं अभिशासन के मुद्दे पर बात करूं, मुझे भारत के वित्तीय परिदृश्य में विधायी आशय और विनियामक अपेक्षाओं दोनों के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के महत्व और एआरसी के लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करनी चाहिए।

दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन में एआरसी की भूमिका

हम सभी जानते हैं कि हमारे वित्तीय संस्थानों के बही-खाते क्रेडिट जोखिम के प्रति काफी संवेदनशील हैं क्योंकि परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा ऋण और अग्रिम से बनता है। वास्तव में, क्रेडिट जोखिम भारित परिसंपत्ति (क्रेडिट आरडब्ल्यूए) बैंकिंग प्रणाली के कुल आरडब्ल्यूए का लगभग 80 प्रतिशत है। इसलिए, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और गैर-बैंकों के बही-खातों में क्रेडिट जोखिम के समक्ष वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की सुरक्षा के लिए कोई भी विवेकपूर्ण विनियमन बना रहना चाहिए।

क्रेडिट चक्र में चार अलग-अलग चरण शामिल हैं। इनमें ऋण प्रस्ताव लाने; मूल्यांकन और हामीदारी; संवितरण और निगरानी; और, अंततः पुनर्भुगतान जिसके बाद क्रेडिट चक्र का अगला चरण शुरू होता है, शामिल है। हालाँकि, यदि किसी कारण से, उधारकर्ता समय पर बकाया का भुगतान नहीं करता है और ऋण चौथे चरण में प्रवेश नहीं करता है, तो समस्या हो सकती है। इस समय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एआरसी को संस्थागत किया गया है। ये दबावग्रस्त वित्तीय संपत्तियों को अपने कब्ज़े में लेकर ऋण प्रवर्तकों को ऋण देने के अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती हैं। एआरसी ढांचा भी बनाया गया है ताकि यदि संभव हो तो उधारकर्ताओं को अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य कुछ मायनों में ऋण से उत्पन्न उत्पादक परिसंपत्ति को संरक्षित करना भी है।

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। एआरसी से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेषज्ञता से लैस होकर संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली और पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाएं और उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्ज़ा करके बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने में मदद करें।

हालाँकि, ऐसे सभी प्रयासों की प्रभावशीलता अभिशासन की आधारशिला पर निर्भर करती है। इसलिए, आज के संबोधन में, मैं एआरसी के लिए उभरते विनियामक ढांचे और एआरसी के पारदर्शी और प्रभावी कामकाज के लिए मजबूत अभिशासन संरचनाओं की आवश्यकता क्यों है, इस पर बात करना चाहूँगा।

एआरसी के लिए विनियामक ढांचा

एआरसी के लिए कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनका समाधान विनियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए:

- सबसे पहले, एआरसी के पास परिसंपत्ति पुनर्निर्माण व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए।
- दूसरा, संव्यवहार पारदर्शी और स्वतंत्र आधार पर किए जाने चाहिए।
- तीसरा, एआरसी द्वारा किसी परिसंपत्ति के समाधान करने के तरीके को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हमारे सभी विनियम इन मुद्दों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं।

पर्याप्त संसाधन होने के पहले मुद्दे पर, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चूंकि एआरसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के व्यवसाय में हैं, अतः इसके लिए उनके पास संसाधन और आवश्यक क्षमता दोनों होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 मई 2024 को मुंबई में आयोजित 'एआरसी में अभिशासन - प्रभावी संकल्पों की ओर' सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया गया। इस भाषण के इनपुट अनुज शर्मा और प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए थे।

मजबूत और पर्याप्त संसाधन आधार है, शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) की आवश्यकताओं को 100 करोड़ से रु. 300 करोड़[1] तक बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार, इसमें बने रहने के लिए क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, एआरसी को प्रत्येक योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए एसआर के प्रत्येक वर्ग में निरंतर आधार पर, यानी मोचन तक अनिवार्य रूप से कुछ राशि निवेश[2] करनी होगी।

पारदर्शिता के दूसरे मुद्दे पर कई विनियामक व्यवस्थाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए, उधारदाताओं द्वारा एआरसी को परिसंपत्ति हस्तांतरित करते समय एक्सपोज़र की कीमत का पता लगाने, सुरक्षा प्राप्तियों के मूल्यांकन और पारदर्शी प्रकटीकरण के संदर्भ में नियंत्रण प्रदान करने के लिए ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण (एमडी-टीएलई) पर निर्देश। इसके अलावा, दुर्भावनापूर्ण इरादे से युक्त किसी भी लेनदेन से बचने के लिए एआरसी से मानक खातों को लेना विशिष्ट शर्तों के अधीन है। साथ ही, एआरसी और ऋणदाता के बीच हस्तांतरित एक्सपोज़र की वसूली से अधिशेष का बंटवारा वसूली-योग्य आधार पर किया जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार, पारदर्शिता में सुधार की दृष्टि से, संशोधित ढांचे में कई उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं - (i) प्रस्ताव दस्तावेज़ में सुरक्षा प्राप्ति (एसआर) धारकों के लिए प्राप्त रिटर्न के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में प्रकटीकरण; (ii) एआरसी के पिछले प्रदर्शन की प्रकटीकरण अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना; और, (ii) एसआर धारकों के लिए एसआर की रेटिंग के पीछे की धारणाओं और तर्क का प्रकटीकरण। इन उपायों से योग्य खरीदारों (क्यूबी) के व्यापक समूह से निवेश प्राप्त होने, एआरसी और एसआर धारकों के बीच सूचना विषमता का समाधान होने, एआरसी के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए परिसंपत्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एआरसी को प्रेरित करने की संभावना है।

तीसरा मुद्दा अर्जित संपत्तियों के समाधान से संबंधित है। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक विनियामक ढांचे की व्यवस्था है, जो एआरसी को समाधान करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में गतिविधियों को लेकर चिंताएँ हैं जो मुख्य रूप से एआरसी मार्ग से संबंधित हैं जिससे 'भ्रष्ट' प्रमोटरों, जो कि पहले स्थान पर मूल इकाई के डिफ़ॉल्ट के लिए जिम्मेदार थे, को प्रवेश के लिए एक माध्यम मिल जाता है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में धारा 29ए की शुरूआत के बाद से यह पहलू विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे प्रमोटरों को बाहर रखना था। हालाँकि, अक्सर, संस्थाएँ बिना किसी स्वतंत्र सत्यापन के केवल संभावित खरीदार द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा प्राप्त करके इस आवश्यकता को पूरा करती हैं।

जहां, वर्तमान विनियमों का उद्देश्य मोटे तौर पर ऊपर उल्लिखित तीन मुद्दों का समाधान करना है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जो विनियामक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक ऋण समुच्चय के लिए परिचालन लचीलेपन से संबंधित है। उदाहरण के लिए, मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, एक एआरसी दूसरे एआरसी से वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त कर सकती है लेकिन जब अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति एक एआरसी द्वारा दूसरे एआरसी को बेची जाती है, तब मौजूदा एसआर धारकों को प्रभावी रूप से बाहर निकलना होगा। इस संदर्भ में, सुझाव दिए गए हैं कि एसआर को समाप्त किए बिना, एक एआरसी से दूसरे एआरसी में ट्रस्टी/प्रबंधक की भूमिका में बदलाव की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, ऋण समुच्चय और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए, ऐसी मांग है कि संकटग्रस्त कंपनी से संबंधित इक्विटी को भी ऋणदाताओं द्वारा कर्ज़ सहित एआरसी को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां एआरसी को विभिन्न चैनलों जैसे आईबीसी या कर्ज़ को इक्विटी में परिवर्तित करने के माध्यम से इक्विटी हासिल करने और उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व/नियंत्रण का विस्तार करने की अनुमति है, उन्हें व्यवसाय की बिक्री/पट्टे सहित निर्णय लेने की परिचालन स्वतंत्रता की अनुमति दी जानी चाहिए।

[1] संदर्भ: DoR.SIG.FIN.REC.75/26.03.001/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर 2022 (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12399)

[2] एआरसी, निधि अंतरण कर, एसआर में अंतरणकर्ता के निवेश का न्यूनतम 15% या जारी किए गए कुल एसआर का 2.5%, जो भी अधिक हो, प्रत्येक योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए एसआर के प्रत्येक वर्ग में ऐसी योजना के तहत जारी किए गए सभी एसआर के मोचन तक निरंतर आधार पर निवेश करता रहेगा।

[3] वर्तमान में, एआरसी को अपने स्वयं के ऋण के हिस्से को उधारकर्ता इकाई की इक्विटी में परिवर्तित करने की अनुमति है और आईबीसी के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करते समय, वे उधारकर्ता इकाई की इक्विटी हासिल कर सकते हैं।

हम इन मुद्दों की जांच कर रहे हैं और अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए उद्योग जगत के संपर्क में हैं।

अभिशासन की भूमिका

लेकिन एक प्रमुख क्षेत्र है जो विनियामकों के रूप में हमारे लिए चिंता का विषय है, वह है एआरसी में अभिशासन।

सुदृढ़ और पुष्ट अभिशासन एआरसी को एक मजबूत बिजनेस मॉडल बनाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इस संदर्भ में, अभिशासन, मात्र विनियामक अनुपालन से परे जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के दर्शन का प्रतीक है। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले में, जहां हितों का टकराव अधिक होता है और वैश्वासिक कर्तव्यों का परीक्षण किया जाता है, वहाँ प्रभावी अभिशासन एआरसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में विश्वास पैदा करने में मदद कर सकता है।

सुदृढ़ अभिशासन ढाल और तलवार दोनों के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह हितधारकों को हितों के टकराव से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि निर्णय विवेक और ठोस व्यावसायिक समझ द्वारा निर्देशित हों। साथ ही, यह निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर और नैतिक नेतृत्व की संस्कृति को बढ़ावा देकर पारदर्शिता और जवाबदेही की तलवार चलाता है।

अभिशासन की मजबूत आधारशिला बनाने के लिए निम्नलिखित स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं:

i. प्रभावी निगरानी वाला एक विविध और स्वतंत्र बोर्ड
ii. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो में निहित जोखिमों की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन्हें कम करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा
iii. परिचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और लेखांकन प्रथाओं के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में पारदर्शिता
iv. निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हितों के टकराव की पहचान करने, उनका प्रकटीकरण करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय और मजबूत नीतियां
v. एक व्यापक आचार संहिता जो नैतिक सिद्धांत, पेशेवर अखंडता और जवाबदेही को रेखांकित करती है।

इसलिए, एआरसी में सुदृढ़ अभिशासन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें उपर्युक्त सभी तत्व शामिल हों। इस संबंध में एआरसी के बोर्डों और शीर्ष पदाधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्हें इन सिद्धांतों के आधार पर एक मजबूत और सुदृढ़ संस्थागत संस्कृति विकसित करनी होगी। सुदृढ़ अभिशासन तंत्र के बिना, एआरसी के लिए अपने परिचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विश्वास पैदा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

एआरसी को संकटग्रस्त उधारकर्ताओं के सामने अपने आचरण के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। यहां तक कि कदाचार की एक भी घटना संभावित रूप से विवाद का कारण बन सकती है, जिससे इस क्षेत्र को बचना चाहिए। जहां हम अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए एआरसी के अधिकारों को स्वीकार करते हैं, वहीं उन्हें या उनके वसूली एजेंटों को उधारकर्ताओं के उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए। एआरसी के लिए एक व्यापक उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) लागू की गई है जिसके लिए एआरसी को पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है। वर्तमान समय में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां एआरसी द्वारा अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों में खुदरा ऋण की हिस्सेदारी बढ़ गई है (31 मार्च, 2020 के 9% से 31 मार्च, 2023 के 16% तक)।

आगे का रास्ता

जैसा कि आप जानते हैं, एआरसी के विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक समिति (अध्यक्ष: श्री सुदर्शन सेन) द्वारा की गई थी। इन सिफारिशों के आधार पर हमने अक्तूबर 2022 में संशोधित अनुदेशों का एक सेट जारी किया और बाद में उन्हें 24 अप्रैल 2024 को जारी एआरसी पर व्यापक मास्टर दिशानिर्देशों में भी शामिल किया गया है। इन निर्देशों का उद्देश्य एक मजबूत अभिशासन प्रणाली स्थापित करना है। इसे सक्षम करने की दृष्टि से और बोर्ड की निगरानी बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एआरसी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करना होगा, और किसी भी बोर्ड की बैठक में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। एआरसी को बोर्ड की दो समितियों, ऑडिट समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करना है, जिनसे

बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि होगी और विशिष्ट क्षेत्रों पर इसके केंद्र में सुधार हो सकता है।

हालाँकि, हमने पाया है कि सभी एआरसी ने बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली पर संशोधित दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया है। मैं इस अवसर पर सभी एआरसी से इन दिशानिर्देशों को यथोचित रूप से लागू करने का आग्रह करूंगा। इसके अलावा, विनियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने में विफलता और जानबूझकर उल्लंघन करने पर, यदि आवश्यक हो, सख्त पर्यवेक्षी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

एआरसी दिशानिर्देशों में संशोधन के अलावा, रिज़र्व बैंक क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण के लिए एक जीवंत बाजार बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण और मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) और द्वितीयक बाजार ऋण संघ (एसएलएमए) के गठन पर संशोधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में उठाए गए कुछ हालिया कदम हैं।

आरबीआई विनियमों का जोर मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और समाधान में विशेषज्ञता रखने वाले अतिरिक्त हितधारकों को शामिल करने पर विचार करके संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक बाजार विकसित करने पर है। यह आशय दबावग्रस्त परिसंपत्ति ढांचे के प्रतिभूतिकरण पर चर्चा पत्र में परिलक्षित होता है। इससे संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की अपेक्षा है, जिससे संस्थाओं को बेहतर समाधान और पुनर्प्राप्ति तंत्र के साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और इष्टतम परिणाम प्राप्त होंगे। इस क्षेत्र में उनके पहले प्रस्तावक लाभ को देखते हुए, मुझे लगता है कि एआरसी इस केंद्रित क्षेत्र को भुनाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं और उन्हें उचित गंभीरता से इस व्यवसाय क्षेत्र के इर्द-गिर्द विकल्प तलाशने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

अंत में, मैं इस तथ्य को दोहराना चाहता हूं कि आरबीआई विनियमों का उद्देश्य इस क्षेत्र की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। एआरसी क्षेत्र के नेताओं के रूप में, आपका प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि यह क्षेत्र विधायी और विनियामक आशय के माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम पर केंद्रित रहे और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआरसी के कामकाज और शासन मानकों के बारे में कोई भी नकारात्मक धारणा दूर हो जाए।

इसे प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि एआरसी के पास मजबूत अभिशासन ढांचा, सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, सुविकसित जोखिम प्रबंधन कार्य और मजबूत अनुपालन संस्कृति हो। एक विनियामक के रूप में, हमारा प्रयास परिचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के तीव्र और कुशल समाधान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सहयोग प्रदान करना होगा। मुझे उम्मीद है कि एआरसी इस प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएगी।

धन्यवाद।